भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2757 का उत्तर

रेल परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब

2757. डॉ॰ एम.के॰ विष्णु प्रसादः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में हुए विलंब के कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे रह गई हैं तथा परियोजना-वार लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सुधारात्मक उपाय करने और बाधाओं को दूर करके परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए किसी निगरानी समिति का गठन किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): इस समय, 189 नई लाइनें, 55 आमान परिवर्तन और 247 दोहरीकरण परियोजनाओं सहित कुल 491 रेलवे परियोजनाएं निष्पादन/योजना/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

6.476 लाख करोड़ रु. की लागत वाली इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 48860.64 किमी है जिनमें से 9113 किमी लंबाई पर कार्य शुरू हो गया है मार्च, 2019 तक कुल 1.43 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

mm

2009-10 के दौरान, प्रति वर्ष 1519.8 किमी. की औसत दर से 7599 किमी. (1727 किमी. नई लाइन, 3997 किमी. आमान परिवर्तन और 1875 किमी. दोहरीकरण परियोजनाएं) शुरू की गई हैं। 2014-15 के दौरान प्रति वर्ष 2625 किमी. की औसत दर से 13124 किमी. (3035 किमी. नई लाइन, 3993 किमी. आमान परितर्वन और 6096 किमी. दोहरीकरण परियोजनाएं) शुरू की गई, जो 2009-14 के दौरान शुरू की गई लाइन का 172% है।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर), विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, परियोजना के शीघ्र निष्पादन के लिए राज्य सरकार का सहयोग और उत्साह, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल, माननीय न्यायालय के आदेश, जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंत में पूरा होने की स्थिति पर गणना की जाती है।

समग्र राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं बिना लागत में वृद्धि के पूरी हो जाएं, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय से पहले भी पूरी हो जाती हैं, रेलवे ने निविदा में बोनस क्लॉज के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन की अवधारणा को अपनाया है जो परियोजना के निष्पादन की गति में और वृद्धि करेगा।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

*****

mm